

## RAJYA SABHA

Monday, 16th December, 1991-25 Agra-ha-yana, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the Clock,  
Mr. Chairman in the Chair.

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में बहराइच में पर्यटक गृह का निर्माण

\* 341. श्री आनन्द प्रकाश गौतम : क्या नागर विमानन और पर्यटक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती बुद्ध स्थल के निकट एक उत्तम किस्म के पर्यटक गृह के निर्माण के लिये 13.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस परियोजना के लिये कितना धन उद्दिष्ट किया गया है तथा अब तक कितना धन दिया जा चुका है ; और

(ङ) इसके निर्माण के लिये कब तक का समय निर्धारित किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अ० एच० फारूख) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

#### विवरण

(क) जी हां, सरकार ने एक पर्यटक परिसर का निर्माण करने के लिए 12.583 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निर्माण करने पर आपत्ति इस आधार पर की थी कि अधिगृहीत भूमि को संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है ताकि प्राचीन स्थल और इसके पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके ।

(घ) पर्यटक परिसर 63.00 लाख रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया था और भारत पर्यटन विकास निगम को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए 20.00 लाख रुपए अवमुक्त किए गए थे ।

(ङ) इस परिस्थिति में निर्माण कार्य के लिए कोई समयावधि निर्धारित कर पाना कठिन है ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीय सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से हमारे देश के पर्यटन स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और शायद इसी दृष्टिकोण से भारतीय पर्यटन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती बुद्ध स्थल पर एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाने का निर्णय लिया था । अभी जो प्रश्न का उत्तर आया है उसमें यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहां पर जो भूमि अधिगृहीत की है उस पर निर्माण कार्य करने पर इस आधार पर आपत्ति की है कि भूमि को संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है ।

मंत्री महोदय से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर चाहुंगा कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है वह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के बारे में, और पर्यटन स्थल के बनाने के बारे में जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है वह कार्रवाई सम्पन्न हो गई है अथवा नहीं हुई है ? और इसके सम्पन्न होने में जो काश्तकारों को मुआवजा देने की बात है और भूमि को अपने कब्जे में लेने की बात है तो क्या यह कार्रवाई हो चुकी है ? और तीसरे उसके बाद यह नोटिस दिया गया है कि यहां पर इस को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है या नहीं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिधिया) : सर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब आपत्ति उठाई तो उसके पश्चात् एक उच्च स्तरीय टीम ने दुबारा एक वैकल्पिक साइट सोचने का प्रयास किया। उसको आईडेंटिफाई करके प्रदेश सरकार को यह जानकारी दी गई। यह नवम्बर, 1988 में टोप गई थी। इसके पश्चात् कई रिमाइन्डर्स भेजे गये और काफी रिमाइन्डर्स के पश्चात् स्टेट गवर्नमेंट ने यह जानकारी हमें दी कि अब स्टेट पी०डब्ल्यू०डी० जिसकी जमीन थी वह अब इस जमीन को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। क्योंकि यह निःशुल्क जमीन आई०टी०डी०सी० को दी जानी थी इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने हम को यह भी जानकारी दी कि 11.42 लाख रुपये पी०डब्ल्यू०डी० को दे दिये गये हैं। पर अभी भी अतिरिक्त भूमि लेने से रह गई है जो लगभग साढ़े 4 एकड़ है जिसका अधिग्रहण अभी नहीं हुआ, ट्रांसफर अभी नहीं हुआ और इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट से। उनको याद दिला रहे हैं पर जो पर्याप्त एक रिस्पॉस उनका होना चाहिए वह हमें नहीं मिल रहा है। तो शायद इसलिए हो सकता है कि प्रदेश सरकार ने दूसरी भूमि अधिग्रहण की है और वहां वे प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रण दे रहे हैं। उनसे चर्चा हो रही है। होटल लगाने की बात हो सकती है और यहीं इसका कारण हो। परन्तु हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास है कि इसको विकसित किया जाये। जब तक हमको जमीन उपलब्ध नहीं होगी तब तक विकसित करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि हम शुरूआत का कार्य नहीं कर पाएंगे। जहां तक धनराशि का सवाल है, माननीय सदस्य को जवाब में जानकारी दे दी गई है कि 63 लाख रुपये इसके लिए स्वीकृत किये गये हैं और 20 लाख रुपये आई०टी०डी०सी० को डिपार्टमेंट आफ टूरिज्म कई वर्ष पहले दे चुका है। हम लोग कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर जमीन जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो तो हम कार्य शुरू कर पाएंगे।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी की तरफ से नहीं आई है कि इस योजना में अधिग्रहण की कार्यवाही को कब शुरू किया गया था? यह प्रश्न मैंने पहले पूछ लिया था कि यह कार्यवाही आपने कब शुरू की है और इसको कितना समय हो गया है, अभी तक इसमें कार्यवाही नहीं की गई है। अगला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि जो भूमि संरक्षित करके प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की गई है और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि दूसरे स्थल पर पर्यटन स्थल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है और यह जो दूसरी योजना बनी है उसमें वे कितनी भूमि लेना चाहते हैं? क्या उस भूमि का कोई निर्देशन हुआ है और अगर वह भूमि प्राइवेट सेक्टर की है तो उसके अधिग्रहण की कार्यवाही का क्या कोई प्रारम्भिक कार्य हुआ है?

श्री माधव राव सिधिया : महोदय, मैं कह चुका हूँ कि जो वैकल्पिक भूमि है उसका क्षेत्र लगभग 6 एकड़ है और इसमें से लगभग साढ़े चार एकड़ भूमि अभी भी बचाया है और कुछ धनराशि जो पी०डब्ल्यू०डी० को दी गई है वह साढ़े चार एकड़ मिलने के पश्चात् छः एकड़ में से है। जो पैमेन्ट हुई है वह जमीन अभी नहीं दी गई है। अतिरिक्त साढ़े चार एकड़ की भी पैमेन्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो जाएगी तो उसके पश्चात् ही जमीन ट्रांसफर की जाएगी और तभी कार्य शुरू कर सकते हैं। नवम्बर, 1988 में हमारी हाई लेवल टीम वहां गई थी, तब से स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा चल रही है। यह काफी पुराना मामला है। दिसम्बर 1988, जनवरी 1989, अप्रैल 1989, जून 1989, अगस्त 1989, दिसम्बर, 1989 और सितम्बर, 1990 में हमने रिमाइन्ड किया है। मैं मान यह संकेत दे रहा हूँ कि बहुत गम्भीरता हम इस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं। हमारा पूरा निर्णय है कि इसको विकसित करें। इसके लिए जमीन मिलना अति आवश्यक है और अनिवार्य है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : मैंने यह जानना चाहा था कि अधिग्रहण की कार्य-वाही शुरू हुई है या नहीं ?

श्री माधव राव सिधिया : जैसा मैंने कहा, अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट को करना है। 11.42 लाख रुपये दे दिये गये हैं। अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट को करना है और उसके बाद ही जमीन ट्रांसफर होगी।

श्री बेकल "उत्साही" : हमारे अजीज दोस्त गौतम साहब ने सही कहा है कि यह बुद्ध स्थली तिहायत ही अहम है। हम तो वहीं 6-7 किलोमीटर पर रहते हैं और अच्छी तरह से इस बारे में जानते हैं। इसके पहले जब सेंट्रल विभाग की कंसल्टेटिव कमिटी में था तो मैंने कई सजेरन्स दिये मैं और एक रनवे बनाने का भी सजेरन दिया था, जो स्वीकार किया गया था। यह श्रावस्ती वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने बैठ कर 24 वर्ष तक अपने भिक्षुओं को दीक्षा और शिक्षा दी थी। इस तरह से वह बड़ा अहम और जल्दो स्थान है। जिसको डेवलपमेंट दिया जाये और विकसित किया जाये। हम जानते हैं कि जो जमीन एक्वायर की गई थी वह बिलकुल अलग-अलग थी। हमारे पुरातत्व विभाग के लोगों ने न जाने क्यों इसको रोका और आपत्ति की। अब जो जमीन एक्वायर की जा रही है। वहां पर पी०डब्ल्यू०डी० का स्टेट हाउस है। वहां पर हमारे यालो आते हैं। वह बहुत ही खराब हालत में है, उसमें रहते हैं, इसका दूसरे देशों पर क्या असर पड़ता होगा ? इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह रनवे स्वीकार हो चुका है और उसके निर्माण का क्या सिलसिला है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पर्यटन विभाग द्वारा जो योजना बनाई जा रही है उसके लिए भूमि बहुत ही नाकाफी है, यह बात माननीय मंत्री जी ने भी कही है। उसके विकास के लिए हमारे पुरातत्व विभाग के और जापान के पुरातत्व स्कालर भी गये थे और खुदाई भी कर रहे थे।

श्री बिकल "उत्साही" : हमारे عزیز دوست گوتم صاحب نے صحیح کہا ہے کہ یہ بڑا اہم اور تاریخی مقام ہے۔ ہم تو وہیں چھ سو سات کلومیٹر پر رہتے ہیں۔ اور ابھی طرح سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے پہلے جب میں ٹورزم ڈیپارٹمنٹ کی کونسلٹیو کمیٹی میں تھا تو میں نے کئی تجاویز دیئے تھے۔ اور ایک رن وے بنانے کا بھی مشورہ کیا دیا تھا۔ جو سوسپلر کیا گیا تھا۔ یہ شہر اسی کی سطح پر ہے جہاں پر ہمارا تادمہ نے بیٹھ کر ۲۴ برس تک اپنے باعشوروں کو دیکھا اور شکشا دی تھی۔ اس طرح سے وہ بڑا اہم اور ضروری استھان ہے جس کو ڈیولپمنٹ دیا جائے۔ اور وکست کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو زمین ایکواائر کی گئی تھی وہ بالکل الگ تھلک تھی۔ ہمارے پیراتوو ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں نے نہ جانے کیوں اس کو روکا اور آہنی کی طب جوزین ایکواائر کی جائز ہے وہاں پر پی۔ ڈبلیو۔ ڈی کارپسٹ ہاؤس ہے۔ وہاں پر ہمارے یاتری آتے ہیں۔ وہ بہت ہی خراب حالت میں ہے۔ اس میں لوگ رہتے ہیں اسکا دوسرے دیشتوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ اسلئے میں یہ چھنا چاہتا ہوں کہ کیا رن وے سوسپلر ہو چکا ہے اور اس کے نرمان کا کیا سلسلہ ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ

परमेश्वर और ब्रह्मांड के अंतर का जो प्रश्न है, वह भी  
 इस के लिये बहोली बहुत ही नाकामी है।  
 बात नानिने मन्त्री जी ने कही है।  
 के उकास के लिये भारत में ब्रह्मांड के  
 और जापान के ब्राह्मणों के अंतर को  
 क्लृप्त कर देते हैं।

वह भी यह तय नहीं कर सके कि आया  
 गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम वहाँ पर थे  
 या नहीं। हम तो यह जानते हैं...

श्री श्री "असाही" : वह भी नहीं  
 को आगोतम बुद्ध, महात्मा गौतम  
 नहीं, हम तो यह जानते हैं...

श्री सभापति : इसने अभी तय नहीं  
 किया कि महात्मा बुद्ध वहाँ गये थे या  
 नहीं। अभी भी कोई डाउट है क्या ?

श्री डेक्ल "उरसाही" : इनको डाउट  
 है। इसीलिए कि वे कहते हैं कुशाण  
 पौरिख और गुप्त पौरिख की सारी  
 चीजें मिल रही हैं। उसके पहले का तो  
 कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमारे खुद  
 के पुरातत्व वाले वहाँ गये थे। जापान  
 के स्कावर अभी तक इन मंजिल पर  
 पहुँचे ही नहीं हैं जो वह यह साबित कर  
 सकें कि महात्मा बुद्ध वहाँ बैठे भी थे।  
 वह दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक  
 तो वह है जिसको हम अपनी जुवान में  
 सहेट कहते हैं और दूसरा है सहेट।  
 बीच में किसी वक्त नदी बहती थी।  
 यह इतना बड़ा स्थान है लेकिन वहाँ पर  
 टुरिज्म विभाष है ही नहीं। सिर्फ  
 हाटिकल्चर के लोग हैं जो कुछ पीछे  
 लगा रहे हैं। ऐसा हमें महसूस हो रहा  
 है कि स्टेट और सेंटर इन दो पार्लों  
 के बीच में यह स्थान पिस रहा है और

उसका डवलपमेंट रुक रहा है। मैं मंत्री  
 महोदय से पूछना चाहता हूँ कि कब तक  
 इसको आप विनिसित करेंगे ?

श्री श्री "असाही" : उन को डाउट है।  
 इस लिये कि वे कहते हैं कि कान  
 गिफ्ट पर मिण्ट की सारी चीजें मिल रही हैं।  
 इस से पहले का तो कुछ मिल ही नहीं रहा है।  
 भारत के ब्राह्मणों के अंतर को  
 जापान के अंतर को भी तक इस मंजिल पर  
 सिंचे ही नहीं हैं। जो वे यह साबित कर सकें  
 महात्मा गौतम वहाँ बने थे। वहाँ दो हिस्सों  
 में बंटा हुआ है। एक तो वह है जिस को हम  
 जापान से सहेट कहते हैं और दूसरा है  
 सहेट। बीच में किसी वक्त नदी बहती थी।

यह इतना बड़ा स्थान है लेकिन वहाँ पर  
 टुरिज्म विभाष है ही नहीं। सिर्फ  
 हाटिकल्चर के लोग हैं जो कुछ पीछे  
 लगा रहे हैं। ऐसा हमें महसूस हो रहा  
 है कि स्टेट और सेंटर इन दो पार्लों  
 के बीच में यह स्थान पिस रहा है और

SHRI M.O.H. FAROOK : Sir we  
 share the views of the hon. Member  
 about the importance of this Place  
 They have no doubt about the genui-  
 neness of the place. As far as we are  
 concerned, we have no doubt about the

genuineness of the place. It all depends upon the State Government to provide us the land. As soon as they provide us the land, we will take necessary steps.

MR. CHAIRMAN : He wants to know about the air strip.

SHRI M.O.H. FAROOK : There is no proposal for an air strip.

श्री माधव राव सिधिया : जहाँ तक एयर स्ट्रिप का स्थल है पूरा क्षेत्र जो है, परम पूजनिय गौतम बुद्ध जहाँ-जहाँ गये थे, जहाँ-जहाँ उन्होंने निवास किया, जापान की एक योजना है उनके अन्तर्गत यह आ रहा है। इसमें एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और एक हिस्सा बिहार में है। आदिस्ती भी इसी स्कीम के अन्तर्गत आती है। हम लोगों ने भी प्रपोजल रखा था कि आदिस्ती में एयर पोर्ट भी हो और रेलवे भी हो। पर जापानी टीम, जिसने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गंभीरता से इसकी स्टडी की है उसका यह कहना है कि वहाँ पर रेलवे बेस्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको बहुत बड़ी स्कीम है। लगभग 170 करोड़ रुपये की वह स्कीम है। जापानी टीम ने इस प्रपोजल को रोजेक्ट कर दिया है। इसलिये वहाँ पर अभी कोई रेलवे का प्रपोजल नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम : माननीय सभापति महोदय, भारत अपनी संस्कृति के लिये सारे विश्व में बहुत पुराने समय से जाना जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध के दर्शन और उनके संदेश ने भारत को सारे संसार में गौरवान्वित किया है। मेरे दोस्तों ने अभी बताया कि वर्षों तक महत्त्वा गौतम बुद्ध ने वहाँ पर दीक्षायें और शिक्षायें दी और पंचशील को उन्होंने सारे संसार में ध्वजा फहराई। उसी पंचशील के नारे को लेकर तत्कालीन चीन के प्रधान मंत्री और पंडित नेहरू के बीच संधि हुई। आज भी चीन के प्रधानमंत्री ली-फांग ने भी पंचशील को बोहराया है। महोदय, वैसे भी यह बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी वर्ष है जिन्होंने बुद्ध धर्म का पुनरुत्थान इस देश में किया। तो मेरा मंत्री जी ने प्रश्न है कि जब बौद्ध धर्म इतना सार्थक उस समय था और आज भी जब इसकी महत्ता बढ़

रही है और बौद्ध धर्म के मानने वाले देशों से इतनी भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वह इस स्थान का विकास करे और वहाँ पर हवाई पट्टी बनाये, टूरिस्ट होम बनाये? यह जो बहस करते हैं कि इसमें लैंड एक्विजिशन की परेशानी है तो I want to remind the hon. Minister that section 17 of the Land Acquisition Act of Uttar Pradesh authorises the Government to take immediate possession.

तो आप क्यों नहीं उसका तुरंत पंजेशन लेते हैं, क्यों नहीं उसका मूआवजा आप तय करते हैं?... (व्यवधान)

श्री बी० नरायणस्वामी : लैंड एक्विजिशन ऐक्ट की बात नहीं है... (व्यवधान)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Listen to me.

This is part (a) of my question.

Part (b) of my question is :

माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान) ... वहाँ पर श्रीलंका द्वारा संचालित एक इंटरमीडिएट विद्यालय बना हुआ है, वहाँ पर बौद्ध विहार बना हुआ है। आपको क्या परेशानी टूरिस्ट होम बनाने में हो रही है, आप उसका टूरिस्ट महत्त्व का स्थल क्यों नहीं बनाते?

श्री सभापति : सेंटर लैंड एक्वाइर कर सकता है, क्या आपके पास कोई प्रशार्टी है?

श्री माधव राव सिधिया : सभापति महोदय, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा इच्छुक हैं कि वहाँ टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बहुत प्रयास करना चाहते हैं और धृष्टता भी कर रहे हैं। परन्तु टूरिस्ट होम हवा में नहीं बनाया जा सकता है। जब तक हम को जमीन न मिले और यह स्टेट गवर्नमेंट के अन्तर्गत आता है। स्टेट गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कर के हम को हैंड ओवर करे तो इस टूरिस्ट कम्प्लेक्स बना देंगे।

**श्री संघ प्रिय गौतम :** स्टेट गवर्नमेंट को ग्राप एडवांस कम्प्लेशन जमा कराइये, पैसा दीजिए (व्यवधान)

**श्री राम नरेश यादव :** सभापति जी, गौतम जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। महात्मा बुद्ध का संदेश जो उन्होंने पूरे विश्व को दिया था, केन्द्र सरकार ने जिस तरह से उस स्थान पर पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लिया था उस निर्णय के आधार पर जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू हुई लेकिन कुछ शोक लग गई। फिर एक टीम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भेजी गई। उस ने इस बात का प्रयास किया कि कहीं दूसरी जगह पर वहाँ जो पी०डब्ल्यू० डी० का इन्स्पेक्शन हुआ है, निरीक्षण भवन है, उसको एकबापर करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। इस तरह की केन्द्रीय सरकार की मंशा है कि महात्मा बुद्ध जैसे महान दार्शनिक, धर्म के प्रणेता को स्मरण करने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको सम्मान देने के लिए इस तरह की यहां व्यवस्था की जाए। माननीय मंत्री जी ने यह भी अपने उत्तर में कहा कि हमने नवम्बर, 1988 से ले कर सितम्बर, 1990 तक बहुत से रिमाइंडर भी भेजे लेकिन प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार भी चिंतित है तथा हमारे सम्मानित सदस्य गौतम जी और दूसरे भी जानते हैं जिनकी सरकार वहाँ पर है तो क्या मंत्री जी द्वारा इतने स्थल के विकास को ध्यान में रखते हुए, महात्मा बुद्ध की उस स्थली का जिस तरह से विकास करना चाहते हैं, इस गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए क्या आप उत्तर प्रदेश के ट्यूरिज्म मंत्री को बुला कर के या उनके साथ बैठ कर के इस प्रश्न को जल्दी हल करेंगे? मेरे प्रश्न का भाग (ब) यह है कि क्योंकि इस में इतना विलम्ब हो रहा है इसलिए विलम्ब के आधार पर एक बार बैठ कर निर्णय ले लिया जाना चाहिये। यह भी बिलकुल सही बात है कि यह जापान से मिली हुई योजना है क्योंकि जापान में आज भी

जिस तरह से बुद्ध धर्म की पूजा होती है और उनकी एक योजना भी है। इसको ध्यान में रखते हुए इस बात को जल्दी से तय करा के सदन को आश्वस्त करेंगे कि हम इतने दिनों तक इस निर्माण कार्य को सारी बाधाओं को दूर करने के बाद पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे और सदन को अवगत कराने का प्रयास करेंगे? मेरे प्रश्न का भाग (स) यह है कि जमीन जो नहीं मिल पा रही है उस जमीन को जल्दी से जल्दी लेने के लिए क्या आप प्रदेश की सरकार को जो धनराशि दी जानी है वह दे कर के उसको इस लायक बनाने का काम करेंगे ताकि वह आपके ऊपर आरोप न लगा सके?

**श्री माधव राव सिधिया :** सभापति महोदय, हमें कोई धनराशि राज्य सरकार को नहीं देनी है। उनको यह जमीन निशुल्क देनी है। इसलिए उनकी जो जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है उसे जल्दी से निवटा लें और इस ओर निश्चित रूप से जैसे माननीय सदस्य ने कहा हम लोग पूरी तरह से तत्परता के साथ उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कुछ सुनवाई करेंगे हालांकि हम ग्राह-दस बार उनको लिख चुके हैं। शायद प्रत्यक्ष रूप से हमारी कुछ सुनवाई हो। दूसरी बात जो आपने पूछी थी, आप तीन चार सवाल पूछ चुके हैं।

(व्यवधान)

**श्री राम नरेश यादव :** हमने प्रश्न को (अ), (ब) और (स) कर के पूछा है। हमने यह भी पूछा था कि कब तक आप ट्यूरिज्म मंत्री से मिल कर के इस बात का निर्णय कर लेंगे। आप तबतक यह कार्य जिस गंभीरता से कर रहे हैं, इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कब तक आप निर्माण करा लेंगे?

**श्री माधव राव सिधिया :** इसके बारे में मैं निश्चित रूप से फिर लिखूंगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब भी नें दिल्ली आने के लिए तैयार

है, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, इस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक टारगेट या लक्ष्य निर्धारित करने का सवाल है। टारिफ़ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो नीति निर्धारित कर सकता है और अपनी इच्छुकता व्यक्त कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट से भर्चा कर सकता है पर अंतर्नीयता मुख्य जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है क्योंकि लैंड, पावर, कस्ट्रक्शन ये सब बातें स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं और कई बार हमको विकतों और कठिनाइयों को सह्यूस करना पड़ता है अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित करने में, इसीलिए कोई टारगेट (व्यवधान)

श्री रास नरेश यादव : कब तक बात हो जाएगी क्योंकि सामला बहुत गम्भीर है।

श्री समापति : ये कैसे बता सकते हैं ?

इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबन्ध

\* 342. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :

श्री सुरेन्द्रजित सिंह अहलुवालिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इराक पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण वहाँ दवाइयों और खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता के कारण लाखों बच्चे और वृद्ध व्यक्ति मर रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इन संबंध में लिखा है

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAV SINH SOLANKI) : (a) Government is aware of the serious situation within Iraq caused by UN economic sanctions against that country and the acute shortages of essential commodities, including food and medicines.

† सभा में यह प्रश्न श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल द्वारा पूछा गया।

(b) Being alive to the humanitarian aspects of the situation, India has consistently advocated at the United Nations Security Council, easing of sanctions against Iraq, which would enable imports into Iraq of food, medicines and other essential commodities.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मोहतरिम चैयरमैन साहब, आपकी तवस्सुत से मैं वजीरे खारिजा ने जो जवाब दिया है उसके बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ तवज्जह दिलाकर इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मोहतरिम वजीर ने जवाब दिया है कि हुकूमते हिंद इस बात से बाखबर है कि इराक के अंदर बूढ़े, जवान और बच्चे बीमारी से, दवाइयों की कमी से और खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से मारे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर बराबर इस बात की कोशिश हुकूमते हिंद की तरफ से होती रही है कि वहाँ जो परेशानी है, इराक के अंदर, उसको कम करने की कोशिश की जाए और दवाइयाँ और खाने की चीजें वहाँ एकतापेट हो सकें या वहाँ तक पहुँच सकें। इसकी सरकार ने वकालत की है। मैं इसी संबंध में इसी ताल्लुक से मोहतरिम वजीर से यह पूछना चाहूँगा कि गुजिश्ता दो हफ्ते पहले हिंदुस्तान की पालियामेंट के 51 मेम्बराने पालियामेंट ने एक मेमोरेण्डम या एक एहतिनाजी खत यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को लिखा था। इसमें राज्य सभा और लोक सभा के 51 मेम्बराने पालियामेंट शामिल थे। इस पर दस्तखत करने वाली पार्टियों के नाम थे—जनता दल, सी०पी० आई० “एम०”, सी०पी०आई०, डी०एम०के०, समाजवादी जनता दल और भारतीय जनता पार्टी.. (व्यवधान) मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि इस खत को बी०बी०सी० ने नश्र किया, वाइस आफ अमेरिका ने नश्र किया, दूरदर्शन ने भी नश्र किया। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है और अगर जानकारी है तो इस सिलसिले में मंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस को लिखित रूप में क्या कार्यवाही की है या क्या रिक्वेस्ट की है वह बताना गवारा करेंगे ? लिखित रूप में उन्होंने क्या काम किया है। चूँकि सवाल का जवाब दिया है कि यूनाइटेड नेशंस में